(d) if so, the details of the agencies competent to examine the credibility?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) Yes, Sir.

(b) Operating Agency, appointed by BIFR, prepares the revival package for sick companies as per the guidelines issued by BIFR Bench.

(c) The revival package prepared by the Operating Agency on the basis of the guidelines issued by the Bench is examined by the Bench and the copy of the Scheme with modifications, if any, made by the Board is sent as a draft scheme to the sick company and the Operating Agency and all the other concerned parties inviting suggestions and objections within the time specified by the Bench. The approved draft scheme is also published in newspaper (both National and local dailies) so as to give it wider publicity. On the basis of the suggestions and objections, if any, received either from the company or any other party, necessary modifications are incorporated in the scheme and the same is thereafter sanctioned by the Board under Section 18(4) of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 and would come into force on such date as the Board may specify and it is binding on all parties concerned.

(d) Under Section 25(1) of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, any person aggrieved by an order of the Board made under this Act may, within 45 days from the date on which a copy of the order is issued to him, prefer an appeal to the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction.

ज्ञानपीठ पुरस्कार

733. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लेखकों, और कवियों को पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और 1993, 1994 तथा 1995 के वर्षों के दौरान "ज्ञानपीठ पुरस्कार "हेतु प्रस्तावित लेखकों के नाम क्या थे तथा उपर्युक्त तीनों में किन-किन व्यक्तियों को अंततः यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, और

(ख) क्या हिन्दी साहित्य के लेख "श्री ज्ञानपीठ पुरस्कार" हेतु कभी प्रस्ताव किया गया था, यदि हां, तो किस वर्ष के लिए तथा उन्हें यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया था ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग और संस्कृति (विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 1994 से अस्तित्व में आए भारतीय ज्ञानपीठ नामक एक गैर सरकारी न्यास द्वारा वर्ष 1965 से एक वार्षिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है । संस्कृति विभाग की पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा करने, नाम सुझाने अथवा चयन करने में कोई भूमिका नहीं होती है ।

विश्व पुस्तक मेले में गांधी जी पर लिखित पुस्तकों की बिक्री

734. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व पुस्तक मेले मेंराष्टपिता महात्मा गांधी वध क्यों" तथा उनकी हत्या के सह-अभियुक्त गोपाल गोडसे की पुस्तक "गांधी वर्ध और मैं" बेची जा रही थी,

(ख) यदि हां, तो उक्त पुस्तकों का मूल्य तथा उनके प्रकाशक का नाम क्या है और उनकी कुल कितनी प्रतियां बेची गई,

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई, और

(घ) क्या पाकिस्तान तथा श्रीलंका के प्रकाशक इस पुस्तक मेले से नाराज थे, यदि हां, तो उनकी नारा नाराज़गी के क्या कारण थे और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा0 कृपा सिन्धु भोई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा दी गई सूचनानुसार सूर्य-भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित "गांधी-वध क्यों" की करीब 100 प्रतियां और गोपाल गोडसे द्वारा लिखित "गांधी वध और में" की 50 प्रतियां क्रमशः 35/- रुपये और 100/- रुपये के मूल्य पर 12वें विश्व पुस्तक मेले में बेची गई थी ।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को इन दोनों पुस्तकों के प्रदर्शन और विक्रय पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि कानूनी रूप से इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था ।

(घ) जी, नहीं । मेले में जिन प्रकाशकों ने भाग लिया था वे सामान्यतः पुस्तक मेले से प्रसन्न थे । तथापि कुछ विदेशी भागीदारों ने अपने प्रेषित माल की जांच/सीमा शुल्क अनुमति के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है । विदेशों से बड़ी संख्या में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार को घटनाये अपरिहार्य हैं क्योंकि इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है ।

Occuplion of Quarters by Employees of Ashoka Hotel

735. SHRI GAYA SINGH:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1502 given in the Rajya Sabha on 12th December, 1995 and state:

(a) whether it is a fact that in cases of forcible occupation, provisions of (Eviction of Unauthorised Occupants) Act. 1971, arc applicable;

(b) the total amount recoverable from those 58 forcible Ooccupants ans damages calculated under the said Act, in each case;

(c) the reasons for not recovering damages from these occupants;

(d) whether it is a fact that some such occupants of Type C quarters in Ashoka Hotel, have sublet the quarters to outsiders; and

(c) if so, what action has been taken against them by the management?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) Yes, Sir. The provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 arc applicable in cases of unauthorised / forcible occupation of staff quarters. Keeping in view industrical relation problems and business interests, only persuasive efforts hae been made and legal action of filing cases before the Estate Officer under the said Act has not been resorted to so far. Since action has not been taken under the said act, the question calculation of damages does not arise.

(d) and (c) The Hotel Management received a complaint in Nov, 95 elleging that one of the unauthorised occupants has sublet the staff quarters. The complaint is being investigated by Vigilance Department of Ashok Hotel. On allegations being substantiated, necessary action would be taken against the concerned employcc(s), as per rules.

Demand for one-rank one-pension for Ex- servicemen

736. SHRI SARADA MOHANTY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the one-rank one-pension demand of the Ex-servicemen of the Army has been fully met;

(b) whether there are any anomalies in Government formula to meet their demands;

(c) what is the number of Ex-servicemen on Pension today; and

(d) what would be the recurring expenditure per annum if their demands arc accepted?

THE MINSITER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPTT. OF DEFENCE AND THE DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT) (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) The scheme for one Time Increase (OTI) in pension to pre 1.1.86 Defence pensioners was sanctioned by the Government on 16.3.1992. Government have been receiving representations from ex-Servicemen and their Associations about certain anomalies in the scheme. To examine